



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1174]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

का.आ. 1398(अ).—रॉक्सी ग्रामोद्योग समिति, हरी नगर, पी.ओ. पुरकाजी, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) को 14,78,842.61 रुपए (चौदह लाख अठतर हजार आठ सौ बयालीस रुपए और इकसठ पैसे मात्र) की राशि जिसमें तारीख 27-01-2010 तक ब्याज और दंड ब्याज शामिल है, का भुगतान किया जाना है;

और खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 29 के उप-नियम (1) के अधीन तारीख 24 फरवरी, 2004 को उक्त समिति को एक सूचना भेजी गई थी जिसमें यह निदेश दिया गया था कि इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उक्त समिति आयोग को इस राशि का भुगतान करे, जिसके असफल रहने पर आयोग भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूली करने की कार्यवाही करेगा;

और उक्त समिति ने आयोग को देय 14,78,842.61 रुपए (चौदह लाख अठतर हजार आठ सौ बयालीस रुपए और इकसठ पैसे मात्र) की राशि की अपनी भुगतान देयता का विरोध किया है।

अतः अब, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61), की धारा 19-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आयोग को उक्त समिति द्वारा देयताओं के भुगतान के प्रश्न का विनिश्चय करने को, एक व्यक्ति से गठित अधिकरण का गठन करती है जिसमें अर्थात् श्री एस.के. गोयल, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 होंगे।

2. यह अधिकरण राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 मास के अंदर केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. सी-18019/16/2009-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

S.O. 1398(E).—Whereas, a sum of Rs. 14,78,842.61 (Rupees fourteen lakh seventy eight thousand eight hundred forty-two and paise sixty-one only) including interest and penal interest as on 27-01-2010, is payable by the Roxy Gramodyog Samiti, Hari Nagar, PO Purkaji, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said Society), to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

As whereas, a notice was served on the said society under sub-rule (1) of rule 29 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 dated the 24th February, 2004 directing the said Society to pay the sum due to the Commission within 30 days from the receipt of the notice failing which the Commission shall proceed to recover the same as arrears of land revenue;

And, whereas, the said Society has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 14,78,842.61 (Rupees fourteen lakh seventy-eight thousand eight hundred forty-two and paise sixty one only) which is due to the Commission.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19-B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri S.K. Goyal, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011, to decide the question on the payment of dues by the said Society to the Commission.

2. The Tribunal shall submit its report to the Central Government within three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F.No. C-18019/16/2009-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.